

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

संशोधन प्रार्थना पत्र संख्या 89/2013/जोधपुर  
सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी  
घट द्वितीय, प्रतिकरापवंचन, पाली

अपीलार्थी

बनाम

मैसर्स कांकरिया मशीनरी स्टोर  
जोधपुर

प्रत्यर्थी

एकलपीठ  
श्री सुनील शर्मा, सदस्य

उपरिस्थित

श्री जमील जई  
उप राजकीय अभिभाषक  
श्री आर.आर.सिंघवी  
अभिभाषक

अपीलार्थी की ओर से

प्रत्यर्थी की ओर से

निर्णय दिनांक : 18.08.2015

निर्णय

यह संशोधन प्रार्थना पत्र प्रत्यर्थी व्यवहारी की ओर से राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर की एकलपीठ द्वारा अपील संख्या 2112/2012/जोधपुर सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट द्वितीय, प्रतिकरापवंचन, पाली बनाम मैसर्स कांकरिया मशीनरी स्टोर, जोधपुर में पारित निर्णय दिनांक 28.06.2013 में संशोधन हेतु प्रस्तुत किया गया है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि कर निर्धारण अधिकारी ने दिनांक 7.12.2011 को परिवहन चेकिंग के दौरान वाहन संख्या आरजे-19-1जी/4360 की जांच किये जाने पर सबमर्सिबल पम्प सेट नरोडा (अहमदाबाद) से जोधपुर लाया जाना पाया गया। उक्त माल के सम्बन्ध में दस्तावेज मांगे जाने पर इनवाइस संख्या 289 दिनांक 6.12.2011 एवं बिल्टी संख्या 3234 दिनांक 6.12.2011 प्रस्तुत किये गये। दस्तावेजों की जांच पर कर निर्धारण अधिकारी ने परिवहनित माल के दौरान घोषणा पत्र वैट-47 होना आवश्यक है, उसके अभाव में राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे अधिनियम कहा जायेगा) की धारा 76 (2) सपठित नियम 53 के प्रावधानों की अवहेलना मानते हुए वाद के निस्तारण हेतु प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को स्थानान्तरित कर दिया। उक्त तथ्यों के आधार पर कर निर्धारण अधिकारी ने प्रत्यर्थी को कारण बताओ नोटिस जारी किया। नोटिस की पालना में प्रस्तुत जवाब को अमान्य करते हुए सबमर्सिबल पंप सेट (पम्प मय इलेक्ट्रिक मोटर) पर अधिनियम की धारा 76 (6) के अन्तर्गत शास्ति रु. 1,80,165/- आरोपित कर आदेश दिनांक 7.12.2011 पारित किया। कर निर्धारण अधिकारी के उक्त आदेश के विरुद्ध प्रत्यर्थी व्यवहारी ने अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत की। अपीलीय अधिकारी ने सबमर्सिबल पंप सेट (पम्प मय इलेक्ट्रिक मोटर) को अधिसूचित वस्तु की श्रेणी में नहीं मानते हुए वैट-47 की आवश्यकता नहीं मानकर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा



आरोपित शास्ति को अपास्त कर दिया। अपीलीय अधिकारी के आदेश दिनांक 30.4.2012 से व्यथित होकर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा कर बोर्ड के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर, कर बोर्ड की एकलपीठ द्वारा निर्णय दिनांक 28.06.2013 पारित कर, कर निर्धारण अधिकारी की ओर से प्रस्तुत अपील अस्वीकार कर दी गई, जिसमें संशोधन हेतु प्रार्थना पत्र प्रत्यर्थी व्यवहारी की ओर से प्रस्तुत किया गया है।

प्रत्यर्थी व्यवहारी की ओर से विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि कर बोर्ड का निर्णय दिनांक 28.06.2013 अपील के आधारों पर पारित नहीं किया जाकर मौखिक बहस के आधार पर पारित किया गया है, जो रिकार्ड की परिलक्षित भूल की श्रेणी में आने से निर्णय दिनांक 28.06.2013 संशोधनीय है। उनका कथन है कि निर्णय दिनांक 28.06.2013 के पेज तीन के अन्तिम पैरा दिया गया निष्कर्ष पूर्ण निष्कर्ष नहीं है क्योंकि "समरसेबल पम्प" वैट-47 के लिए अधिसूचित वस्तु नहीं है, इसलिए निर्णय दिनांक 28.06.2013 तथ्यों एवं बहस के विरुद्ध होने के कारण संशोधन योग्य है। उनका कथन है कि अपीलीय अधिकारी का आदेश पूर्ण रूप से तथ्यों पर आधारित है, जिसके अनुसार समरसेबिल पम्प वैट-47 के उद्देश्य के लिए न्यायिक दृष्टान्त 92 एस टी सी 312 के प्रकाश में अधिसूचित वस्तु नहीं है, इसलिए निर्णय दिनांक 28.06.2013 संशोधनीय है। उन्होंने उक्त कथन के आधार पर कर बोर्ड के निर्णय दिनांक 28.06.2013 में रिकार्ड से परिलक्षित भूल होने संशोधन प्रार्थना पत्र स्वीकार करने का निवेदन किया।

राजस्व की ओर से विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने संशोधन प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए संशोधन प्रार्थना पत्र अस्वीकार करने का निवेदन किया।

उभय पक्ष की बहस सुनी गयी तथा उपलब्ध रिकार्ड एवं निर्णय दिनांक 28.06.2013 का अवलोकन किया गया। संशोधन प्रार्थना के सम्बन्ध में व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक का कथन है कि "समरसेबल पम्प" वैट-47 के लिए अधिसूचित वस्तु नहीं है, इसलिए निर्णय दिनांक 28.06.2013 तथ्यों एवं बहस के विरुद्ध होने के कारण संशोधन योग्य है। कर निर्धारण अधिकारी के आदेश दिनांक 07.12.2011 के अनुसार माल मालिक को सुनवाई का अवसर दिये जाने पर भी वैट-47 पेश नहीं किया गया, बल्कि बिना वैट-47 के लाये जाने की गलती स्वीकार कर प्रस्तुत जवाब के साथ घोषणा पत्र संख्या 7069665 प्रस्तुत किया गया है, जिसकी आवश्यकता नहीं होने के आधार पर अपीलीय अधिकारी ने कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आरोपित शास्ति को अपास्त किया है, जिसके विरुद्ध कर निर्धारण अधिकारी की ओर से अपील प्रस्तुत करने पर कर बोर्ड द्वारा अपास्त की गई है, जिससे व्यवहारी के अभिभाषक द्वारा अपील प्रस्तुत सुनवाई के समय प्रस्तुत किये गये तर्कों को ही स्वीकार किया गया है। एकलपीठ



द्वारा दिये गये निर्णय दिनांक 28.06.2013 में संशोधन किये जाने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना सुसंगत नहीं है।

इस सम्बन्ध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी बनाम मक्कड प्लास्टिक एजेन्सी (टैक्स अप डेट 29 पेज 353) के प्रकरण में पारित किये गये को उद्धृत किया जाना समीचीन होगा, जिसमें मत प्रतिपादित किया गया है कि चेतन मस्तिष्क के पारित किये गये निर्णय में संशोधन किया जाना उचित नहीं है, जिसका सारगर्भित अंश उद्धरित किया जाना समीचीन है :-

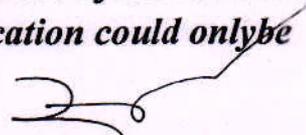
*“The scope and ambit of the power which could be exercised under section 37 of the Act of 1994 is circumscribed and restricted within the ambit of the power vested by the said Section. Such a power is neither a power of review nor is akin to the power of revision but is only a power to rectify a mistake apparent on the face of the record. Rectification implies the correction of an error or a removal of defects or imperfections. It implies an error, mistake or defect which after rectification is made right.*

*In the case of Commissioner of Income Tax, Bhopal v. Ralson Industries Ltd. reported in (2007) 2 SCC 326 a similar situation arose for the interpretation of this Court regarding the scope and ambit of Section 154 of the Income Tax Act vesting the power of rectification as against the power vested under Section 263 of the Income Tax Act, which is a power of revision. While examining the scope of the power of rectification under Section 154 as against the power of revision vested under Section 263 of the Income Tax Act, it was held by this Court as follows at Para 8:-*

*“8. The scope and ambit of a proceeding for rectification an order under section 154 and a proceeding for revision under Section 263 are distinct and different. Order of rectification can be passed in certain contingencies. It does not confer a power of review. If an order of assessment is rectified by the Assessing Officer in terms of Section 263 is exercised by a higher authority. It is a special provision. The revisional jurisdiction is vested in the Commissioner.*

*An order thereunder can be passed if it is found that the order of assessment is prejudicial to the Revenue. In such a proceeding, he may not only pass an appropriate order in exercise of the said jurisdiction but in order to enable him to do it, he may make such enquiry as he deems necessary in this behalf.”*

*In paragraph 12 of the said judgment it was also held that when different jurisdictions are conferred upon different authorities, to be exercised on different conditions, both may not be held to be overlapping with each other. While examining the scope and limitations of jurisdiction under Section 154 of the Income Tax Act, it was held that such a power of rectification could only be*



*exercised when there is an error apparent on the face of the record and that it does not confer any power of review. It was further held that an order of assessment may or may not be rectified and if an order of rectification is passed by the Assessing Authority, the rectified order shall be given effect to. We may also at this stage appropriately refer to yet another decision of this Court in Commissioner of Trade Tax, U.P v Upper Doab Sugar Mills Ltd. reported in (2000) 3 SCC 676, in which the power and scope of rectification was considered and pitted against the scope of review. The aforesaid decision was in the context of Section 39(2) of the U.P. Sales Tax(Amendment) Act, 1995 which provides the power of review. Section 22 of the said Act provides for rectification of mistake. In the said decision, it was held that when two specific and independent powers have been conferred upon the authorities, both powers can be exercised alternatively, but, it cannot be said that while exercising power of rectification, the authority can simultaneously exercise the power of review.*

*Both the aforesaid two decisions which were rendered while considering taxation laws are squarely applicable to the facts of the present case, it is also now an established proposition of law that review is a creature of the statute and such an order of a review could be passed only when an express power of review is provided in the statute. In the absence of any statutory provision for review, exercise of power of review under the garb of clarification/modification/correction is not permissible. In coming to the said conclusion we are fortified by the decision of this Court in Kalabharati Advertising V. Hemand Vimalnath Naruichania and Others reported in (2010) 9SCC 437. Section 37 of the Act of 1994 provides for a power to rectify any mistake apparent on the record. Such power is vested on the authority to rectify an obvious mistake which is apparent on the face of the records and for which a reappreciation of the entire records is neither possible nor called for. When the subsequent order dated 22-01-2009 passed by the Taxation Board is analysed and scrutinized it would be clear/apparent that the Taxation Board while passing that order exceeded its jurisdiction by re-appreciating the evidence on record and holding that there was no mala fide intention on the part of assessee-respondent for tax evasion. Such re-appreciation of the evidence to come to a contrary finding was not available under Section 37 of the Act of 1994 while exercising the power of rectification of error apparent on the face of the records. Thus, the orders passed by the Taxation Board on 22-01-2009 as also impugned order and judgment passed by the High Court upholding the said order of the Taxation Board are hereby set aside and*

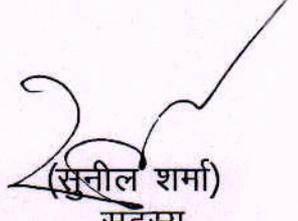
25

***quashed and the original order passed by the Assessing Officer is restored.***

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित उपरोक्त सिद्धान्त के आलोक में चैतन्य मस्तिष्क से पारित किये गये आदेश को इस स्तर पर विधिक रूप से संशोधित नहीं जा सकता है।

उपरोक्त विवेचित तथ्यों के आधार पर अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत किये गये संशोधन प्रार्थना पत्र को अस्वीकार किया जाता है।

निर्णय सुनाया गया।

  
(सुनील शर्मा)  
सदस्य